विचार बिन्दु

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनिए। –रोबिन शर्मा

कभी अन्नदाता तो कभी आम लोगों को रुलाता टमाटर

यह कैसी विडंबना है कि टमाटर की खेती करने वाले काश्तकारों को आज टमाटर की लागत तो दूर तुड़वाई के पैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं। मध्य प्रदेश की मण्डियों से आ रहे समाचार केवल मध्यप्रदेश के टमाटर उत्पादक किसानों की ही पीड़ा व्यक्त नहीं कर रहे अपितु देश की अधिकांश मण्डियों में टमाटर के भाव औंधे मुंह गिर गए हैं। कुछ समय पहले ही गृहणियों की रसोई में टमाटर का तड़का मुश्किल हो गया था और टमाटर के खुदरा भाव 200 रु. प्रति किलो को छू गए थे आज वहीं टमाटर देश की किसी–किसी मण्डी में तो एक रु. प्रति किलो से भी कम में बोला जा रहा है। ऐसे में किसान अपनी बदनसीबी के आसूं बहाते हुए सड़कों पर फेंकने, पशुओं को खिलाने या मण्डियों में बिखेरने को मजबूर हो रहे हैं। आज गली–मौहल्ले में फेरी लगाकर बेचने वाले सब्जी विक्रेता ही 10 से 15 रु. किलों में टमाटर बेच रहे हैं। खुदरा में टमाटरों के भाव कम होने से आम नागरिकों को तो तात्कालीक फायदा हो रहा है पर उत्पादक किसान अपने आपको ठगा महसूस कर रहा है। यह केवल इस बार की ही समस्या नहीं है अपितु प्रतिवर्ष इस तरह के हालातों से किसानों को दो–चार होना पड़ता है। देखा जाएं तो टमाटर ना कोई से दोस्ती और ना कोई से प्रेम वाली कहावत को चरितार्थ करता रहा है। साल में मौका मिलने पर पहले आम नागरिकों को रुलाता है तो फिर आम लोगों को थोड़ी राहत देते हुए उत्पादक काश्तकारों को रुलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। लगभग यही स्थिति प्याज की कई सालों से चली आ रही है।

जहां तक टमाटर के उत्पादन की बात है तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक टमाटर उत्पादन करने वाला देश है। टमाटर के उत्पादन में भी चीन पहले पायदान पर है तो तुर्की, अमेरिका, मिस्र तीसरे, चौथे और पांचवें पायदान पर है। कहने को तो यह कहा जाता है कि टमाटर का उद्गम देश दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी तटीय प्रदेश माना जाता है। मैक्सिको से टमाटर सारी दुनिया में पहुंचा है। टमाटर धीरे–धीरे रसोई का प्रमुख उपयोगी बन गया। यह भी माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली खोजकर्ताओं के साथ टमाटर ने हमारे देश में प्रवेश किया और आज यह घर–घर की जरुरत बन गया। इसे विलायती भंटा या विलायती बैंगन भी कह कर पुकारा जाता रहा है। छत्तीसगढ़ की जशपुर टमाटर देश की सबसे बड़ी मण्डी मानी जाती है तो आंध्र प्रदेश टमाटर का सर्वाधिक उत्पादक प्रदेश माना जाता है। वैसे टमाटर की पैदावार समूचे देश में होती है और टमाटर के सहउत्पाद खासतौर से टमाटर कैचअप, टमाटर सॉस, टमाटर सूप आदि से कंपनियां बारे न्यारे कर रही हैं।

सवाल यह है कि सरकार को टमाटर या इसी तरह की जल्द खराब होने वाले उत्पादों के रखरखाव और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज युक्त परिवहन वाहनों की संख्या बढ़ानी होगी। सरकार ने भले ही किसानों के उत्पादों को लाने ले जाने के लिए ट्रेन सेवा शुरु कर दी है पर अभी इस दिशा में तेजी से काम करने की आवश्यकता है।

जहां तक टमाटर की गणित समझने का सवाल उठता है विशेषज्ञों का मानना है कि टमाटर की खेती में काश्तकार की एक से दो लाख रु. तक की लागत प्रति एकड आती है और यह भी माना जाता है कि सामान्य परिस्थितियों में 400 से 420 क्विंटल टमाटर की पैदावार काश्तकार प्रति एकड़ तक ले लेते है। अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक बरसात और ओलावृष्टि से सबसे अधिक टमाटर की फसल प्रभावित होती है। कीट प्रकोप के कारण भी टमाटर की पैदावार पर सीध असर पड़ता है। सबसे अधिक चिंतनीय बात यह है कि जब टमाटर की फसल तैयार होकर बाजार में आती है तो टमाटर की भावों में तेजी से गिरावट आने लगती है। इसका व्यापारी दोहरा लाभ उठाते हैं। एक तो ज्यादा से ज्यादा टमाटरों की खरीद कर निजी कोल्ड स्टोरेज में जमा कर देते हैं और मौके–बेमौके बाजार में कृतिम अभाव पैदा कर दोहरा लाभ कमा लेते हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में टमाटर के सहउत्पाद तैयार करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियां बुवाई से पहले ही काश्तकारों से सौदा कर लाभ उठाती है। खैर यह विषयांतर होगा।

टमाटर उत्पादक किसान तुड़वाई या मण्डी तक पहुंचाने की लागत भी नहीं मिलने से परेशान है तो किसान इन हालातों को देखते हुए टमाटर के भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने और सरकारी खरीद की दबी जुवान से बात करने लगे हैं। खैर यह तो अलग बात हुई पर कहीं ना कहीं सरकार को भी साल दर साल होने वाले ऐसे हालातों को देखते हुए किसानों और आमलोगों के हित का रोडमेप बनाना ही होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब सड़कों पर टमाटर बिखरे मिलते हैं तब भी सरकार की साख प्रभावित होती है तो जब टमाटर के भाव आसमान छूने लगते हैं तब भी सरकार की साख पर सीधा–सीधा असर पड़ता है। राजनीतिज्ञ भूले नहीं होंगे प्याज के भावों में उतार–चढ़ाव का असर सरकारों के आने और जाने से जुड़ा रह चुका है। सवाल यह है कि सरकार को टमाटर या इसी तरह की जल्द खराब होने वाले उत्पादों के रखरखाव और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज युक्त परिवहन वाहनों की संख्या बढ़ानी होगी। सरकार ने भले ही किसानों के उत्पादों को लाने ले जाने के लिए ट्रेन सेवा शुरु कर दी है पर अभी इस दिशा में तेजी से काम करने की आवश्यकता है। देश में फूड पार्क बनाने की दिशा में तेजी लानी होगी। सबसे ज्यादा जरुरी सरकार को तत्काल बाजार हस्तक्षेप की और ध्यान देना होगा। एक विंग ऐसी होनी चाहिए कि जो बाजार में मांग और उपलब्धता पर नजर रखे और समय रहते काश्तकारों के लिए जब जरुरत हो तब और आमलोगों के लिए जब जरुरत हो तब कदम उठाएं ताकि किसान, मण्डी और आमलोगों के हितों की रक्षा की जा सके। अब तो यह भी साफ हो गया है कि बाजार में कब अधिक माल आयेगा तो कब किल्लत वाल स्थिति होगी। जब सब कुछ सामने है तो दीर्घकालीन नीति बनाकर दोनों के हितों को ध्यान में रखना होगा।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(वरिष्ठ लेखक)

राशिफल गुरूवार 3 अप्रैल, 2025

पंडित अनिल शर्मा

चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठि तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2082, रोहिणी नक्षत्र प्रातः 7:02 तक, सौभाग्य योग रात्रि 12:01 तक, कौलव करण दिन 10:46 तक, चन्द्रमा सायं 6:22 से मिथुन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य–मीन, चन्द्रमा–वृष, मंगल–कर्क, बुध–मीन, गुरू–वृष, शुक्र–मीन, शनि–मीन, राहु–मीन, केतु–कन्या राशि में।

आज रवि योग प्रातः 7:02 से आरम्भ होगा। आज स्कन्ध षष्ठि व्रत, यमुना जयन्ती, अशोका षष्ठि है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः शुभ सूर्योदय से 7:52 तक, चर 10:58 से 12:30 तक, लाभ–अमृत 12:30 से 3:36 तक, शुभ 5:08 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:20, सूर्यास्त 6:41

मेष
व्यावसायिक कार्यों के लिए यात्रा संभव है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक योजना का क्रियान्वयन होगा। आज आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। नवीन योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। आज मनःस्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

मकर
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

मिथुन
आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय है। घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। वाणी पर संयम रखना ठीक रहेगा।

तुला
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन कार्यों में व्यवधान हो सकता है। व्यावसायिक परेशानियां अभी बनी रहेगी। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

कुंभ
घर–परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख–सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

कर्क
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी बनी रहेगी। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

वृश्चिक
व्यावसायिक आर्थिक मामलों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक आर्थिक विवादों से राहत मिल सकती है। अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।

मीन
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

राजस्थान के युवा अमेरिका में परेशान हो रहे : यह संबंध ठहराव मांगता है

राजेन्द्र मोहन शर्मा

राजस्थान के युवा इंजीनियर रोहित गोठेचा अपनी कम्पनी के काम से अमेरिका में हैं। वे और उन जैसे हजारों युवा राजस्थान सहित अन्य राज्यों से अमेरिका में काम हेतु जाते रहते हैं। लेकिन इस बार जैसा हालात कभी नहीं थे। रोहित गोठेचा कहते हैं यहां अमेरिका में काम कर रहे राजस्थानी और अन्य भारतीय युवाओं में भव का माहौल है। ट्रम्प की वीजा और इमिग्रेशन को लेकर जो आक्रामक नीति है उससे राजस्थानी युवा अन्य देशों का रूख करने को विवश हो गए हैं।

वस्तुतः भारत अमेरिका के सम्बन्धों में वैसी गहराई और ठहराव कभी नहीं रहा जैसा रूस के साथ रहा है। जब सोवियत संघ का जमाना था तब भी और उसके विघटन के बाद रूस बन जाने के बाद। आज भी हमारे रिश्ते रूस से लाजवाब हैं। लेकिन ऐसी सहुलियत अमेरिका के साथ नहीं है। दशकों से हम देख रहे हैं कि अमेरिका भारत का एक विश्वस्त और भरोसेमंद दोस्त कभी नहीं रहा। दोनो देशों के बीच का रिश्ता महज ले दे का रहा है। अमेरिका को भारत के रूप में एक सस्ता बाजार चाहिए और भारत को उन्नत तकनीक, अत्याधुनिक विज्ञान और अद्वितीय हथियार चाहिए। इसी लेन देन पर दशकों से टिके रिश्तों में ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में काफी पेचीदगियां आ गई हैं।

अपने पहले कार्यकाल के मुकाबले ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में काफी आक्रामक और भ्रमित वक्तव्य के लिए कुख्यात हो रहे हैं। "भारत और अमेरिका दो महान लोकतांत्रिक देश हैं"। यह केवल मुहावरा भर रह गया है। भारत का लोकतंत्र ईवीएम अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वाटर मशीन के प्रश्नों के घेरे में उलझा रहता है जिसमें विपक्षी पार्टियां एल एन मस्क और ट्रम्प के ट्वीट को कोट कर पेपर वैलेट की जोर शोर से मांग कर रहे हैं। तथा अमेरिका का लोकतंत्र ट्रम्प के तानाशाही पूर्ण रवैये की भेंट चढ चुका है। हालांकि अमेरिका के इसी महान लोकतंत्र में बाइडेन के मुकाबले पिछली बार हारने वाले ट्रम्प महाशय ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस के सदन में चढ़ाई कर दी थी और परिणाम मानने से इंकार तक कर दिया था। ट्रंप का बेखोफ़ होकर एक के बाद एक चौंकाने वाला और बेहद रिस्की निर्णय यह बता रहा है कि जैसे ट्रंप ने यह सोच लिया हो कि अब अगला कार्यकाल तो मिलने का नहीं है इसलिए कुछ ऐसा कर चलो ताकि इतिहास में ख्यात या कुख्यात किसी न किसी रूप में याद किया जाऊं।

कभी यूक्रेन को धमकी तो कभी गले लगाना, कभी पुतिन से गले लगना और फिर तत्काल ही भारी भरकम पाबंदी घोषित करना, कभी मोदी जी को अपना पक्का दोस्त कहना और अगले ही पल भारतियों को हथकड़ियों में जकड़ना, कभी चीन के साथ नर्मी फिर अगले ही क्षण कड़े तेवर। ये लक्षण एक विचारवान और धीर–गंभीर शासक के नहीं हो सकते। यों तो ट्रम्प के साथ अति आत्मविश्वास का मानसिक असन्तुलन का लेवल चस्पा हो चुका है या फिर अमेरिका को रसातल में पहुंचाने की जिद। यह साफ दिख रहा है कि भारत सरकार एक प्रोटोकॉल के तहत अमेरिकी फैसलों पर सोच समझकर प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य है लेकिन भारतीय जनता नहीं। जो अपमान जनक और बेहूदे निर्णय ट्रम्प ले रहे हैं उससे यह तय है कि भारतीयों की कुदृष्टि ट्रंप को अवश्य लगने को हैं। अमेरिका ने अनेक ऐसी गलतियां कर दी हैं जिससे कि अमेरिका का बर्बाद होना तय कर दिया है। सत्ता में आने के बाद से ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं।

अमेरिका हमेशा से ही एक मिली–जुली संस्कृति का केंद्र रहा है। यहां विभिन्न देशों से लोग आकर कर रहते हैं, और फिर यहीं के नागरिक बन कर रह जाते हैं। यहां के अति आधुनिक संसाधन और प्रतिभाशाली लोगों को अच्छे अवसर बहुत आकर्षित करते हैं। यहां मेहनत करने वालों को बहुत जल्दी सफलता मिलती है। कोई बॉडीबिल्डर यहां आकर बड़ा एक्टर बना सकता है और किसी राज्य का गवर्नर भी बन सकता है। ऐसा किसी और देश में सम्भव नही हो सकता है? यह है अमेरिकन निर्णय और तेज रफ्तार वाला अमेरिका। मगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के साथ अब अमेरिका में सब कुछ तेजी से बदल रहा है। ट्रंप समर्थक अब भारतीयों समेत सभी इमिग्रेंट्स यानी बाहर से आकर बसने वाले लोगों के खिलाफ हैं। वे चाहते हैं कि अमेरिका में बाहर से लोगों का आना बंद हो जाए। वे इमिग्रेशन को अमेरिकियों के लिए नौकरी कम होने, उनकी कम सैलरी और अपराध बढ़ने का कारण मानते हैं।

अमेरिका में मूल अमेरिकी केवल 2 प्रतिशत हैं। बाकी 98 फीसदी लोग कहीं न कहीं से आकर बसे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पिता जर्मन थे। मेलानिया स्लोवेनिया से हैं। वहीं जेडी वेंस स्कॉट्स–आयरिश हैं और उनकी पत्नी भारतीय हैं। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप ने इमिग्रेशन को बड़ा मुद्दा बनाया। चुनाव जीतते ही उन्होंने इमिग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की। इससे हजारों भारतीय भी प्रभावित हुए हैं। ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता में भी बदलाव कर रहे हैं। यह मामला अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में है। ट्रंप मनमर्जी से टैक्स लगा रहे हैं। अगर टैक्स ज्यादा होगा, तो अमेरिका में बाहर से आने वाली चीजें महंगी हो जाएंगी। जो चीजें देश में बनती हैं, उनके दाम भी बढ़ जाएंगे। अभी तो ये टैक्स सिर्फ कुछ चीजों पर ही लगा है, जैसे कार और स्टील। कहीं 10 प्रतिशत तो कहीं 25 प्रतिशत। मगर बाद में कीमतें बढ़ेंगी, 2 अप्रैल से लागू हो सकती हैं।

इसी तरह 1970 के दशक में जब पूरी दुनिया ने जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देना शुरु किया था तब अमेरिका ने इसमें बड़ी भूमिका ग्रहण कर ली थी। अमेरिका ने पर्यावरण संरक्षण एजेन्सी भी बनाई। उसने हवा, पानी और जंगलों को लेकर कानून बनाए। जलवायु संरक्षण पर शोध कार्यों में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। यूनिसेफ की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाया। 2015 में पेरिस समझौता हुआ लेकिन विडम्बना देखिए ट्रंप ने इस पेरिस समझौते से अमेरिका को अलग कर दिया है। क्या पर्यावरण नुकसान से अमेरिका सुरक्षित रह जाएगा। जब पूरी दुनिया तबाह होगी तब अमेरिका कौन से बिल में घुस कर बचेगा।ट्रंप के इस दुराग्रह का असर अमेरिका और कनाडा के करोड़ो लोगों के पीने के पानी की गुणवत्ता पर पड़ने वाला है।

वहां लोग खराब पानी पीने को मजबूर हो जाएंगे। अब वहां कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी को रोकने वाला कोई नहीं है। अमेरिकी शहरों सहित सभी प्राकृतिक जगहों पर फिर से धुंधला आसमान, गंदी नदियां, जहरीला कचरा और कारखानों का गंदा पानी दिखाई देना शुरू हो गया है। जलवायु संकट और गहराने लगेगा। अभी हाल ही में अमेरिका भीषण आग की चपेट आ चुका है। जंगलों लगी आग थमी नहीं है। जिससे अमेरिकियों की सेहत, रोज़गार, शहरों, बुनियादी ढांचे, पेड़–पौधों और जानवरों पर बहुत बुरा असर डालना शुरू कर दिया है। ट्रम्प ने अपने अक्खड़पन का नमूना अमेरिका में शिक्षा विभाग को बन्द करके दिया है। नतीजा होगा शिक्षा की गुणवत्ता खराब होना। क्वालिटी एजूकेशन के लिए हर युग और हर देश में सरकार का समर्थन और सहयोग अत्यावश्यक होता है। एक दौर था जब अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सैनिकों को उच्च शिक्षा के लिए कॉलेजों में भेजा जाता था। वहां आज भी मध्यम वर्ग और पहली पीढ़ी के छात्र कॉलेज जाना एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। अमेरिकी में सभी सरकारें हमेशा से उच्च शिक्षा को समर्थन देती आई हैं। इससे शोध में आगे रहने, काम करने की क्षमता बढाने जैसे फायदे होते हैं। इसमें दूसरे देशों से आने वाले विद्यार्थियों को भी समाविष्ट किया जाता था। मगर ट्रंप ने पूरी बाजी पलट दी है। निश्चित रूप से इससे भारत से जाने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को अब वजीफा नहीं मिलेगा। परिणामस्वरूप अब भारतीय प्रतिभाओं को आर्थिक भार उठाने के लिए खुद को जूझना पड़ेगा जो काफी मुश्किल होगा।

ट्रंप का विश्वविद्यालयों के प्रति उपेक्षा भाव से छात्रों को कम स्कॉलरशिप मिलेंगी तो शोध कार्य भी कम होंगे। शिक्षकों को भारतीय अध्यापकों की तरह अधिक संख्या वाली क्लासों में पढ़ाना होगा। उच्च शिक्षा का महत्व कम हो गया, तो शोध और विकास सहित नए कारोबार तक हर चीज में अमेरिका का पिछड़ तय है। अच्छे कॉलेजों में एडमिशन मिलना, अमेरिका में अमीरी और जन्म के आधार पर बनने वाले नकली अभिजात्य वर्ग को रोकने का एक कारगर तरीका रहा है। मगर अब ये तरीका कमजोर पड़ गया है जिससे समतामूलक समाज बनाना कठिन हो जाएगा। अमेरिका में रह रहे मेरे निकटवर्ती लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहां रह रहे भारतियों में भारी भय व्याप्त है। बहुत से युवा लोगों ने कनाडा सहित अन्य देशों शिफ्ट होना शुरू कर दिया है। भारत के लोग अब ट्रम्प की नीतियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करने लगे हैं। यही समय है जब हमें अमेरिका के उचित विकल्प की राह तलाशनी चाहिए। अमेरिका अपने हितों के लिए भारत से बहुत बड़ी कीमत चाहता है, प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए तैयार नहीं है। भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोलने के खिलाफ रुख अपनाया है, जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। अमेरिका ने भारत पर शुल्क लगाने की धमकी दी है, जबकि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संधियों पर कड़ी नजर रखते हुए व्यापार लाभ सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। उधरअमेरिका को कर्ज देने वाले देशों में चीन–जापान के अलावा भारत भी शामिल है।अमेरिका ने भारत से सैंकड़ो अरब डॉलर का कर्ज ले रखा है। डीडब्लू की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने करीब 234 अरब डॉलर के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड खरीदे हैं। अमेरिका इस पर भी कम ब्याज देना चाहता है।अब आप अमेरिकी दबाव को बखूबी समझ सकते हैं।

–राजेन्द्र मोहन शर्मा,
साहित्यकार, शिक्षाविद् एवं चिंतक

स्कूली शिक्षा की परीक्षा : असर 2024 में राजस्थान का प्रदर्शन

डॉ. सुरेंद्रसिंह शेखावत

कल्पना कीजिए, राजस्थान के किसी दूरस्थ गाँव के सरकारी स्कूल में एक आठ साल का बच्चा बैठा है। उसकी किताबें खुली हैं, लेकिन अक्षर अब भी पहेली बने हुए हैं। कक्षा में शिक्षक की आवाज गूंज रही है, पर समझने और सीखने के बीच अब भी एक लंबी दूरी बनी हुई है। यह केवल एक बच्चे की कहानी नहीं, बल्कि राज्य के लाखों बच्चों की हकीकत है।

वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट असर 2024, जिसे गैर–सरकारी संगठन प्रथम ने जनवरी 2025 में प्रकाशित किया, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति का एक व्यापक आकलन प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में 605 ठाामीण जिलों के 17,997 गांवों से 6.5 लाख बच्चों का सर्वेक्षण किया गया। इस रिपोर्ट में राजस्थान के ग्रामीण इलाकों की शिक्षा व्यवस्था के बारे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि स्कूलों में बच्चे तो हैं, लेकिन शिक्षा अब भी अधूरी है। आइए, इसी संदर्भ में राजस्थान की शैक्षिक स्थिति को कारणों, चुनौतियों और संभावित समाधानों के साथ विस्तार से समझते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में 6–14 आयु वर्ग के बच्चों का स्कूल नामांकन 90 प्रतिशत से अधिक है, जो राष्ट्रीय औसत के करीब है। समठा शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किए गए प्रयासों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हालांकि, 15–16 आयु वर्ग में लगभग 10 प्रतिशत बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो ड्रॉपआउट की गंभीरता को दर्शाता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की ड्रॉपआउट दर 11 प्रतिशत से अधिक है, जो बाल विवाह, घरेलू जिम्मेदारियों, और शिक्षा के प्रति सामाजिक उदासीनता से जुड़ी हुई है। बाड़मेर, जैसलमेर, और सिरोही जैसे जिलों में यह दर और भी अधिक है। सरकारी स्कूलों में नामांकन 2018 के 65 प्रतिशत से बढ़कर 2022 में 70 प्रतिशत हुआ, लेकिन 2024 में यह फिर से 66 प्रतिशत पर आ गया। यह उतार–चढ़ाव निजी स्कूलों की ओर रुझान और सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता की कमी को दर्शाता है।

रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में बच्चों की मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कक्षा 3 के सरकारी स्कूलों के केवल 22 प्रतिशत बच्चे कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं, जो 2022 के 18 प्रतिशत से थोड़ा बेहतर है, लेकिन 2018 के 25 प्रतिशत से भी कम है। इसका मतलब समझिए कि तीसरी कक्षा के तीन चौथाई से अधिक बच्चे पिछली कक्षा की किताब ही नहीं पढ़ पा रहे है।

संख्यात्मकता में भी हालात गंभीर हैं–कक्षा 3 के केवल 30 प्रतिशत बच्चे घटाने जैसे सरल कार्य कर पाते हैं, जो राष्ट्रीय औसत (33.7 प्रतिशत) से नीचे है। कक्षा 5 के स्तर पर यह आंकड़ा और खराब हो जाता है, जहाँ 47 प्रतिशत बच्चे ही कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ पाते हैं और 28 प्रतिशत बच्चे विभाजन कर सकते हैं। राजस्थान में निपुण भारत मिशन के तहत 80 प्रतिशत स्कूलों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफ़ अल एन) गतिविधियाँ शुरू हुई हैं और 70 प्रतिशत शिक्षकों को प्रशिक्षण मिला है, फिर भी अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा है। असर रिपोर्ट ने 14–16 आयु वर्ग के बच्चों की डिजिटल साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया है। राजस्थान में 89 प्रतिशत बच्चों के घरों में स्मार्टफोन उपलब्ध हैं, लेकिन केवल 30 प्रतिशत के पास अपना निजी फोन है। लैंगिक असमानता भी स्पष्ट है–35 प्रतिशत लड़कों की तुलना में केवल 25 प्रतिशत लड़कियों के पास अपना स्मार्टफोन है। 55 प्रतिशत बच्चे इसे शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं, जबकि 78 प्रतिशत सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिवाइस की कमी इसे सीमित करती है।

राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संसाधनों और गुणवत्ता में भारी अंतर बना हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। शिक्षकों की संख्या गुणवत्ता भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि एफ़ अल एन प्रशिक्षण के बावजूद प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा, गरीबी, बाल श्रम और बाल विवाह जैसी सामाजिक–आर्थिक बाधाएँ स्कूल छोड़ने की दर को बढ़ा रही हैं, विशेष रूप से लड़कियों के लिए यह समस्या अधिक गंभीर है। तकनीकी संसाधनों और इंटरनेट की कमी के कारण डिजिटल विभाजन भी बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीण छात्रों को आधुनिक शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। इसके साथ ही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और निपुण भारत मिशन के लक्ष्य जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पा रहे हैं, जिससे सुधार की गति धीमी बनी हुई है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। सबसे पहले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और भर्ती प्रक्रिया को मजबूत किया जाना चाहिए, जिससे शिक्षकों की संख्या और गुणवत्ता दोनों में सुधार हो सके। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाए और सामाजिक बुराई रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु विशेष अभियान चलाए जाएँ। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण स्कूलों में इंटरनेट और स्मार्ट डिवाइस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा सके। इसके अलावा, शिक्षा में स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाई जाए, जिससे अभिभावकों और स्थानीय नेतृत्व को शिक्षा प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जा सके। अंत में, नियमित मूल्यांकन और निगरानी की व्यवस्था की जाए, ताकि प्रगति को ट्रैक किया जा सके और सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें।

असर जैसी रिपोर्ट न केवल शिक्षा व्यवस्था का संतुलित मूल्यांकन प्रस्तुत करती है, बल्कि नीति–निर्माताओं के प्रयासों की प्रगति को भी मापती है। यह स्पष्ट करती है कि राज्य का भविष्य उसकी स्कूली शिक्षा की मजबूती पर निर्भर करता है। यदि राजस्थान को एक समृद्ध और सक्षम समाज की ओर अग्रसर करना है, तो स्कूली शिक्षा में व्यापक और सार्थक सुधार आवश्यक हैं। यह केवल बुनियादी ढांचे या नामांकन दरों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षण गुणवत्ता, समावेशी सीखने के अवसरों और सामुदायिक सहयोग पर भी केंद्रित होना चाहिए। शिक्षा में इन बदलावों से न केवल बच्चों का भविष्य सुधरेगा, बल्कि राज्य की सामाजिक और आर्थिक प्रगति भी सुनिश्चित होगी।

– डॉ. सुरेंद्रसिंह शेखावत,
बीकानेर
(राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता)

कैलादेवी मेले में आज से फिर बढ़ेगी भक्तों की भीड़

मेले के आठवें दिन तक करीब 24 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं

करौली, (निसं.)। कैलादेवी में चल रहे मेले में गुरुवार छठ से एक बार फिर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ेगा। मेले के आठवें दिन तक करीब 24 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।

उत्तर भारत के प्रमुख शक्तिपीठ तीर्थ स्थल आस्था धाम कैलादेवी में इन दिनो मेला चल रहा है। मेले में लघु कुंभ का सा दृश्य देखने को मिल रहा है। चारों तरफ होटल, धर्मशालाओं में ढोल–नंगाडों की गूंज पर नाचते भक्त बाजारों में कैलामाता की जय जयकार करते दिखाई दे रहे हैं। भीड़भाड़ के चलते खेल खिलौने और भोग प्रसाद के दुकानदारों कि अच्छी खासी बिक्री हो रही है दिनभर कैलामैया का भवन माता के जयकारों से गूंजायमान रहता है मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कैलादेवी मंदिर ट्रस्ट प्रबंधन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजग और मुस्तैद नजर आ रहा है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कतारों में मंदिर ट्रस्ट की ओर से पेयजल हेतु ठंडी पानी की निःशुल्क बोतलों का वितरण किया जा रहा है। वहीं माता के दर्शनों के लिए कतारों में लगे भक्तों पर केवड़ा जल का छिड़काव किया जा रहा है। कैलादेवी मंदिर ट्रस्ट के मेला कंट्रोल रूम प्रभारी एडवोकेट संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मेले में आठवें दिन बुधवार तक करीब 24 लाख श्रद्धालु दर्शन लाभ ले चुके हैं। वहीं गुरुवार छठ से लोगों की भीड़ का बढ़ना शुरू होगा जो सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक चलेगी, जिसको देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं।

कैलादेवी मेले के दौरान बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है।